राग दरबारी

ट्रेनों को शादी, शोकसभा के लिए भी दे दीजिए....

रेलवे अधिकारियों को बुलेट ट्रेन की रफ्तार से मीटिंग में पहुंचने का आदेश मिला। एक अधिकारी ने पहला सवाल किया, इतनी इमरजेंसी क्यों? क्या फिर कोई ट्रेन दुर्घटना हो गई? या बारिश के कारण ट्रेनें बंद हो गई हैं?

दूसरे अधिकारी ने कहा, अरे यार, ऐसे फालतू जनहित वाले सवालों के लिए हम कब से दौड़ने लगे?

तभी साहब गंभीर होते हुए बोले, शांत रहिए! रेलवे से जुड़ी एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है। बहुत ही बड़ी...

एक अधिकारी फिर बोल पड़ा, इतनी बड़ी कि उस पर एक साथ दस-बीस रील बनानी पड़ जाए?

बॉस ने झुंझलाकर कहा, उससे भी बड़ी। महाराष्ट्र में एक दंपति ने फर्स्ट क्लास कूपे में डेकोरेटर बुलाकर गुब्बारों और आई लव यू की सजावट करवा दी और उसे हनीमून कोच बना दिया।

एक अधिकारी उत्साहित होकर बोला, ग्रेट, अब लोगों को मनाली, बाली और गोवा जैसे पुराने हनीमून फोटो के बजाय कुछ अलग तस्वीरें देखने को मिलेंगी।

दूसरे अधिकारी ने कहा, वाह, भारतीय सचमुच ट्रेन को अपना घर मानते हैं। रील बनाने के लिए तो यह शानदार आइडिया है।

तीसरे अधिकारी ने कहा, मेरे पास तो आइडियाओं की पूरी एक्सप्रेस है। आखिर कब तक हम लोगों से आरएसी में आधी सीट का पूरा किराया और कैंसिलेशन चार्ज के नाम पर पैसा वसूलते रहेंगे? इससे अच्छा तो ट्रेनों को ही किराए पर वेन्यू की तरह देना शुरू कर दें। जैसे गांव में शादी घर होता है, वैसे ही रेलवे को पूरे देश का चलता-फिरता शादी घर या कम्युनिटी हॉल बना दें। लोग ट्रेन के अंदर ही शादी, गोद भराई, मुंडन, सगाई जैसे कार्यक्रमों के लिए कोच किराए पर ले सकें। मेहमानों के आने-जाने और ठहरने का झंझट भी खत्म। सिंगल डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं, बल्कि मल्टीपल डेस्टिनेशन वेडिंग हो जाएगी।

चौथे अधिकारी ने कहा, मैं तो कहता हूं कि शोकसभा के लिए भी ट्रेन किराए पर दी जा सकती है। आम आदमी सेकंड क्लास में शोकसभा रखे, अमीर लोग फर्स्ट क्लास में और कोई वीवीआईपी हो तो पूरी ट्रेन ही बुक कर ले। शोकसभा की तरह कवि सम्मेलन या मुशायरे के लिए भी ट्रेन किराए पर दी जा सकती है। आखिर शोकसभा हो या कवि सम्मेलन, दोनों जगह ज्यादातर लोगों के चेहरे एक जैसे गंभीर ही दिखाई देते हैं।

पांचवें अधिकारी ने कहा, आजकल नेताओं को सभाओं में भीड़ जुटाने के लिए पूरी-सब्जी खिलानी पड़ती है और 500 रुपए भी देने पड़ते हैं। उससे अच्छा तो ट्रेनें ही भाषण देने के लिए किराए पर दे दी जाएं। नेता जिस तेजी से पार्टियां बदलते हैं, उसी तरह ट्रेन में एक-एक कोच बदलते हुए भाषण देते रहेंगे। बॉस ने चींटी जैसी पतली आवाज में कहा, भाई, रहने दो। यह आइडिया मत देना। अगर मंत्रियों ने रोड शो की जगह ट्रेन शो शुरू कर दिया तो मैं और तुम सब उसी में लग जाएंगे। जैसे लाल सिग्नल मिलते ही ट्रेन रुक जाती है, वैसे ही बॉस की चेतावनी से मीटिंग एक्सप्रेस भी वहीं रुक गई। (हनीमून एक्सप्रेस के रूप में दो घंटे में पहुंचने वाली बुलेट ट्रेन से ज्यादा लोकप्रिय वह हावड़ा एक्सप्रेस होगी, जो 40 घंटे में मंजिल तक पहुंचाती है।)

वीरेंद्र बहादुर सिंह
जेड-436ए, सेक्टर-12, नोएडा-201301 (उ.प्र.)
मो- 8368681336

कार्टून कोना

पेपर लीक के खिलाफ पीसीसी चीफ पटवारी की साइकिल यात्रा आज से

इंदौर से भोपाल तक की 200 किमी की यात्रा करेंगे साइकिल से, हर जिले से करीब 500 साइकिल यात्री यात्रा में जुड़ेंगे

इंदौर। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर ली है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी 14 और 15 जुलाई को इंदौर से भोपाल तक करीब 200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि यह यात्रा युवाओं और अभिभावकों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास है। दो दिवसीय इस अभियान में हजारों साइकिल सवार शामिल होंगे और रास्ते में छात्रों से संवाद भी किया जाएगा।

साइकिल यात्रा की शुरुआत 14 जुलाई की सुबह करीब आठ बजे इंदौर के आरएनटी (रवीन्द्रनाथ टैगोर) मार्ग से होगी। यह क्षेत्र शहर का प्रमुख शैक्षणिक केंद्र माना जाता है, जहां कई शिक्षण संस्थान स्थित हैं। कांग्रेस ने इसी स्थान को इसलिए चुना है ताकि छात्रों के बीच से शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता का संदेश दिया जा सके। पार्टी का आरोप है कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और परीक्षा संबंधी विवादों ने युवाओं का भविष्य प्रभावित किया है।

हर जिले से जुड़ेंगे सैकड़ों साइकिल यात्री

यात्रा इंदौर, देवास, सीहोर होते हुए भोपाल पहुंचेगी। कांग्रेस के अनुसार, रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक जिले से करीब 500 साइकिल यात्री इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। इस तरह इंदौर, देवास, सीहोर और भोपाल को मिलाकर दो हजार से अधिक प्रतिभागियों के साथ यात्रा राजधानी पहुंचेगी। पार्टी ने जीतू पटवारी के साथ पूरे मार्ग में चलने वाले स्थायी साइकिल यात्रियों की अलग सूची भी तैयार की है। इसमें इंदौर के साइकिलिंग ग्रुप और फिटनेस क्लबों के सदस्य भी शामिल रहेंगे।

आष्टा में होगा रात्रि विश्राम

पहले दिन की यात्रा सीहोर जिले के आष्टा कस्बे तक पहुंचेगी, जहां गोकुलधाम मैरिज गार्डन में रात्रि विश्राम किया जाएगा। इसके बाद 15 जुलाई की सुबह कोठरी कस्बे से यात्रा दोबारा शुरू होगी और शाम तक भोपाल पहुंचने का कार्यक्रम है।

समापन स्थल को लेकर प्रशासन से मतभेद

यात्रा के समन्वयक आनंद जाट ने बताया कि कांग्रेस की इच्छा है कि इस अभियान का समापन भोपाल के व्यापमं चौराहे पर हो, क्योंकि व्यापमं प्रकरण को पार्टी युवाओं के भविष्य से जुड़ा बड़ा मुद्दा मानती है। हालांकि प्रशासन ने इस स्थान की अनुमति नहीं दी है। कांग्रेस ने लिली टॉकीज चौराहा और इमामी गेट जैसे वैकल्पिक स्थान भी सुझाए, लेकिन प्रशासन की ओर से मोतिया तालाब के सामने कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव दिया गया है। पार्टी का कहना है कि वहां अस्पताल होने के कारण यातायात और एंबुलेंस सेवाओं पर असर पड़ सकता है।

मुफ्त शिक्षा और पारदर्शी परीक्षाओं की उठाई मांग

जीतू पटवारी ने कहा कि आजादी के 80 वर्ष और प्रदेश में लंबे समय से भाजपा सरकार रहने के बाद अब समय आ गया है कि देश में केजी से पीजी तक गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि छात्रों को सुरक्षित माहौल, निष्पक्ष परीक्षाएं और पारदर्शी चयन प्रक्रिया मिलनी चाहिए। उनके मुताबिक, प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आए विवाद और नीट जैसी परीक्षाओं को लेकर उठे सवाल देश के करोड़ों युवाओं की चिंता का विषय हैं। कांग्रेस इसी संदेश को लेकर युवाओं और अभिभावकों के बीच जाएगी।

भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

पत्रकारों से बातचीत में जीतू पटवारी ने कहा कि हर भाजपा कार्यकर्ता या नेता पेपर माफिया नहीं हो सकता, लेकिन जब भी पेपर लीक या भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, उनमें भाजपा से जुड़े लोगों के नाम चर्चा में क्यों आते हैं। उन्होंने कहा कि इन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। अपने भाई की हिरासत में लिए जाने के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेताओं पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से जनता के बीच अपनी बात रखती रहेगी और कानून पर उसे पूरा भरोसा है।

कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने दिग्गजों की मौजूदगी में दाखिल किया नामांकन

मीनाक्षी नटराजन प्रकरण' से सबक ले उतारे 2 डमी उम्मीदवार

इंदौर। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए सियासी विसात बिछ चुकी है। नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह ने न्यू कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना चुनावी नामांकन पत्र जमा कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस ने न सिर्फ अपनी एकजुटता दिखाई, बल्कि 'मीनाक्षी नटराजन मामले' से सबक लेते हुए बेहद सतर्कता बरती और मुख्य प्रत्याशी के साथ-साथ दो डमी उम्मीदवारों के भी फॉर्म दाखिल करवाए हैं, ताकि किसी भी तकनीकी गड़बड़ी या सियासी उलटफेर की गुंजाइश न रहे।

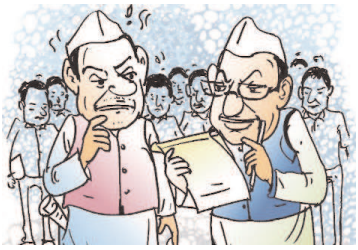

घनश्याम सिंह के नामांकन के दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। उनके साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया, पूर्व मंत्री पी.सी. शर्मा, अशोक सिंह और पूर्व विधायक राजेंद्र भारती मुख्य रूप से मौजूद रहे।

इसके अलावा, नामांकन प्रक्रिया में समाजवादी पार्टी (सपा) के कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जो इस उपचुनाव में कांग्रेस को अपना खुला समर्थन देते नजर आए। एक्जिक्यूटिवब्रांच।

नरोत्तम मिश्रा का दर्द मुख्यमंत्री नहीं बांट रहे

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन कांग्रेस इस चुनाव को मजबूती से जीतेगी।

भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा का दर्द वर्तमान मुख्यमंत्री भी नहीं बांट रहे हैं।

पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने 'थंब्स-अप' (जीत का इशारा) दिखाते हुए दावा किया कि जिस तरह 2023 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, उसी तरह 2026 के इस उपचुनाव में भी कांग्रेस ही परचम लहराएगी।

उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से जनता और कांग्रेस दोनों खुश हैं।

25 हजार वोटों से जीतेंगे

कांग्रेस प्रत्याशी कुंअर घनश्याम सिंह ने कहा कि चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज नामांकन दाखिल कर दिया गया है।

अब कांग्रेस पूरी ताकत (पूरे डैम) के साथ मैदान में उतरेगी। दतिया में पिछले कुछ समय में जो डर और खराब वातावरण बना था, अब उसे सही करने का समय आ गया है। हम यह चुनाव 25,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीतेंगे।

राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय करने की प्रक्रिया शुरू

अब राज्य नहीं दे पाएंगे इससे कम वेतन

इंदौर। श्रम मंत्रालय ने सांविधिक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन (फ्लोर वेज) तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारों के मुताबिक वेतन संहिता के अंतर्गत न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा। अधिकारियों का समूह गणना के तरीके और खपत बास्केट पर काम कर रहा है और केंद्र सरकार 'केंद्रीय सलाहकार बोर्ड' (सीएबी) बनाएगी।

सीएबी राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन की सिफारिश करने से पहले बातचीत करेगा। यह एक बार अधिसूचित होने के बाद न्यूनतम सीमा के लिए कानूनी बाध्यता होगी और राज्य व केंद्र शासित प्रदेश इस निर्धारित सीमा से कम वेतन तय नहीं कर पाएंगे। लोगों ने बताया कि यह तकनीकी प्रक्रिया एस. पी. विशेषज्ञ समूह के तैयार अनुमानों पर आधारित होगी। इस क्रम में खपत बास्केट को नए सिरे से बनाने के बजाए महंगाई के हिसाब से संशोधित किए जाने की संभावना है।

अधिकारियों का समूह तरीके की जांच कर रहा है और खपत बास्केट को अपडेट कर रहा है, जबकि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड केंद्र को अपनी सिफारिश देने से पहले प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करेगा। मामले की जानकारी रखने वाले वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसके साथ ही राज्यों के साथ भी बातचीत चल रही है।

इसका कारण यह है कि न्यूनतम वेतन राशि तय करने में बड़ी चुनौती राज्यों के बीच न्यूनतम वेतन में अंतर है।' खबर लिखे जाने तक श्रम मंत्रालय को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला था।

वोटर लिस्ट में शामिल होने आवेदकों को माता-पिता की एसआईआर की डिटेल देना जरूरी

चुनाव आयोग ने ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया नियम किया लागू

इंदौर। चुनाव आयोग ने ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए नए आवेदकों को पिछली स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान अपने माता-पिता की स्थिति के बारे में जानकारी देनी होगी। अधिकारियों ने बताया कि ये शर्त फॉर्म 6 में जोड़ी गई है। ये वह फॉर्म है जिसका इस्तेमाल पहली बार वोट देने वाले लोग करते हैं जिनके नाम सूची से हटा दिए गए थे और जो दोबारा अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं।

हालांकि, गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए फॉर्म में औपचारिक रूप से कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि यह घोषणा प्रशासनिक निर्देशों के जरिए लागू की गई है और ऑनलाइन सबमिशन के लिए जरूरी कर दी गई है।

अधिकारियों के मुताबिक आवेदक तब तक ऑनलाइन फॉर्म 6 नहीं भर सकते, जब तक वे घोषणा वाला हिस्सा पूरा न कर लें। इस हिस्से में यह जानकारी मांगी जाती है कि क्या आवेदक या उनके माता-पिता का नाम पिछली एसआईआर प्रक्रिया के दौरान तैयार की गई मतदाता सूची में शामिल था या नहीं। ईसीआईएनईटी पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म 6 के भाग जे और के के बीच नई घोषणा में आवेदकों से तीन में से एक विकल्प चुनने के लिए कहा गया है कि क्या उनका अपना नाम पिछली एसआईआर वोटर सूची में था, क्या उनके माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी का नाम पिछली एसआईआर सूची में था, या फिर आवेदक और उनके माता-पिता में से किसी का भी नाम पिछली मतदाता सूची में नहीं था।

अधिकारियों ने बताया कि यह घोषणा पिछले साल जून में शुरू हुई और बिहार एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लागू की गई थी। तब से जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया हुई है, वहां इसे वोटर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाओं में शामिल कर लिया गया है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि बिहार के रोजाना के एसआईआर बुलेटिन में घोषणाओं के साथ भरे हुए फॉर्म दिखाए गए थे। उन्होंने कहा कि इससे वोटरों की पहचान करने में मदद मिलती है और नए वोटरों को आवेदन के साथ जमा करने वाले जरूरी दस्तावेजों की संख्या भी कम हो जाती है।

इस अभियान का मकसद योग्य मतदाताओं की पहचान करना और मतदाता सूची से डुप्लीकेट, मृत, दूसरी जगह चले गए और विदेशी मतदाताओं के नाम हटाना है। पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में एसआईआर अभियान पूरा हो चुका है और अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में ये अभी चल रहा है।